



भारतनेट कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (Digital Communications Commission-DCC) ने सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भारतनेट (BharatNet Programme) के अंतर्गत 2.5 लाख कमी. तार (Fibre) बछाने के कार्य को नज़िी कंपनियों को पट्टे पर देने या बेचने की मुद्रिकरण (Monetize) प्रक्रिया को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

महत्त्वपूर्ण बढि

- डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन द्वारा दूरसंचार कषेत्र के सार्वजनिक उपकरणों को घाटे से उबारने और राजस्व बढाने के उद्देश्य के तहत भारतनेट कार्यक्रम को आगे बढाने के लिये इस कषेत्र में नज़िी कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- एक वरषिठ अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सरकार फाइबर परसिंपत्तियों के प्रभावी उपयोग करने में अक्षम है, इसीलिये इसे नज़िी कंपनियों को पट्टे पर देने अथवा बेचने का प्रस्ताव दिया गया है। हालाँकि कुछ कार्य भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (Bharat Broadband Network Limited) द्वारा भी कयिा जाना सुनिश्चित कयिा गया है।
- आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि इस प्रक्रिया को लीज़ मॉडल के आधार पर शुरू कयिा जा रहा है। इसके लिये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund) को राजस्व आय का अनुमान लगाते हुए 10 दिनों के भीतर एक योजना पेश करने के लिये कहा गया है।

सार्वजनिक उपकरणों की स्थिति

- डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने घाटे में चल रही दूरसंचार कषेत्र के सार्वजनिक उपकरणों (PSUs) जैसे कि BSNL और MTNL को उच्च राजस्व प्राप्त करने की योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। जिसके आधार पर इन उपकरणों द्वारा पुनरुद्धार योजनाओं को प्रस्तुत कयिा गया।
- दोनों फर्मों BSNL और MTNL ने भू-संपत्ति के मुद्रिकरण के साथ साथ कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना (Voluntary Retirement Scheme-VRS) की मंजूरी मांगी है। इस VRS योजना से राजस्व पर क्रमशः 6,365 और 2,120 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।
- एक अनुमान के अनुसार आने वाले 5-6 वर्षों में MTNL के कुल लगभग 22,000 कर्मचारियों में से 16,000 कर्मचारी और BSNL के कुल 1.75 लाख में से 75,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो सकते हैं।

भारतनेट क्या है?

- भारत नेट परियोजना का नाम पहले ओपफसी नेटवर्क (Optical Fiber Communication Network) था।
- भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, कफियती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है।
- इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 mbps तक होगी।
- इसके तहत ज़िला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- इस परियोजना का वित्तपोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा कयिा जा रहा है।
- इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा नज़िी कषेत्र की हसिसेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज़ के कषेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉड बैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
- इस परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये पहुँचाया जाएगा, लेकिन जहाँ ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना संभव नहीं हो, वहाँ वायरलैस एवं सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कयिा जाएगा।
- गाँवों में इंटरनेट पहुँचाने के बाद नज़िी सेवा प्रदाताओं को भी मौके दिये जाएंगे ताकि वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मुहैया करा सकें।
- स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान कयिा जाएंगे।
- भारतनेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।
- भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉड बैंड का लक्ष्य है।

